

ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मनरेगा की भूमिका का समाज शास्त्रीय अध्ययन: रायसेन जिले के पाँच विकासखंडों के विशेष संदर्भ में

जयशील पवार,¹ डॉ. हुदा फैज,²

¹शोधार्थी (सामाज शास्त्र), सामाजिक विज्ञान संकाय, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, भोपाल

²सहायक - प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान संकाय, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश

यह शोध-पत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की समाजशास्त्रीय भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य रायसेन जिले के पाँच विकासखंडों में मनरेगा के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मिश्रित पद्धति (मात्रात्मक-गुणात्मक) से संकलित प्राथमिक व माध्यमिक आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष दर्शाते हैं कि मनरेगा ने रोजगार सुरक्षा, आय-स्थिरता, महिला भागीदारी और सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ किया है; हालांकि भुगतान विलंब, कार्य-गुणवत्ता और निगरानी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

कुंजी शब्दः-- मनरेगा, ग्रामीण श्रमिक, सामाजिक विकास, रोजगार सुरक्षा, रायसेन जिला

1. प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ग्रामीण श्रमिकों की जीवनयात्रा कृषि एवं अनौपचारिक रोजगार की अनिश्चितताओं से प्रभावित रहती है। ग्रामीण जीवन का आधार कृषि, पशुपालन, मजदूरी और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् देश की विकास नीतियों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनता को गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से मुक्ति दिलाना रहा है। परंतु विगत दशकों में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की गति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता बढ़ती गई। विशेषतः भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान और अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसी पृष्ठभूमि में **मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)** की शुरुआत आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी। यह कानून ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का कार्यगारंटी अभियंत्रण उपलब्ध कराता है, जिससे रोजगार, आय, सामाजिक समरसता तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास सम्भव हो सके।

अनुसंधान का उद्देश्यः---

1. मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण श्रमिकों की **आर्थिक स्थिति** में क्या परिवर्तन आया है
2. मनरेगा का ग्रामीण श्रमिकों की आय, रोजगार-दिनों और ऋण-निर्भरता पर प्रभाव।
3. महिला भागीदारी, सामाजिक समावेशन और आत्म-सम्मान पर प्रभाव।
4. इससे ग्रामीण समाज के **सामाजिक विकास और सशक्तिकरण** पर क्या प्रभाव पड़ा है
5. रायसेन जिले के पाँच विकासखंडों में मनरेगा की **कार्यान्वयन गुणवत्ता एवं परिणाम** का तुलनात्मक विश्लेषण।

अनुसंधान प्रश्नः---

- मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की आय और रोजी-रोटी को कितना सुदृढ़ कर पाया?
- क्या मनरेगा ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और जातीय विभाजन कम किया?
- इन पाँच विकासखंडों में मनरेगा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस हद तक प्रभावी रहा?

- मनरेगा से ग्रामीण श्रमिकों की आय-स्थिरता बढ़ी है?
- महिला श्रमिकों की भागीदारी और निर्णय-क्षमता में वृद्धि हुई है?
- विकासखंडों के बीच प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतर है?

2. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

2.1 रायसेन जिले का भू-सामाजिक स्वरूप

रायसेन, मध्य प्रदेश के मध्य-पूर्व भाग में स्थित एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की जनसंख्या ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक है तथा कृषि श्रमिकों तथा कृषि पर आश्रित मजदूरों की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या उल्लेखनीय है। चयनित पाँचों विकासखंडों में कृषि पर निर्भरता अधिक है और मनरेगा कार्य—जल संरक्षण, सड़क, भूमि सुधार—की व्यापकता पाई जाती है।

2.2 निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

- ग्राम्य स्तर पर कृषि अस्थिरता, सीजनल रोजगार की कमी, तथा आर्थिक असुरक्षा प्रमुख समस्याएँ हैं।
- महिला श्रमिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रोजगार अवसरों, सामाजिक बंदिशों और कौशल अभाव के कारण सीमित है।

2.3 अध्ययन के पाँच विकासखंड

विकासखंड	सामाजिक संरचना	कृषि पर निर्भरता	मनरेगा में भागीदारी
बाड़ी	मिश्रित (ओबीसी, अनुसूचित)	उच्च	मध्यम-उच्च
ओबैदुल्लागंज	मिश्रित (खासकर अनुसूचित)	उच्च	उच्च
सांची	मध्यम (कुछ पर्यटन)	मध्यम	मध्यम
सिलवानी	कृषि प्रधान	उच्च	उच्च
उदयपुरा	पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित	उच्च	अच्छा

3. मनरेगा — कानूनी एवं कार्यान्वयन संरचना

3.1 मनरेगा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

यह अध्ययन संरचनात्मक-कार्यात्मकता, सामाजिक समावेशन सिद्धांत तथा सशक्तिकरण दृष्टिकोण पर आधारित है। मनरेगा को ग्रामीण संरचनाओं में कार्य-भूमिका (employment role), न्याय-भूमिका (equity) और समुदाय-भूमिका (community assets) के रूप में समझा गया है।

मनरेगा कानून की शुरुआत 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी हेतु की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न है:

- ग्रामीण घरों को 100 दिनों का गारंटीकृत श्रम;
- कार्य आधारित स्थानीय आधारभूत संरचना का निर्माण;
- गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव को कम करना।

3.2 क्रियान्वयन की रूपरेखा

- ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन एवं कार्य अनुरोध;
- कार्य स्वीकृति समिति के माध्यम से श्रम वितरण;

- मासिक मजदूरी भुगतान और कार्यों का ऑडिट।

3.3 अपेक्षित लाभ

- स्थिर आय स्रोत, सामाजिक समावेशन, महिला मजदूरों को रोजगार में प्रोत्साहन, स्थानीय संसाधन संवर्धन।

4. शोध पद्धति

4.1 अनुसंधान डिज़ाइन

यह एक मिश्रित (Quantitative + Qualitative) अध्ययन है, जिसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार, क्षेत्रीय अवलोकन एवं दस्तावेज विश्लेषण शामिल हैं।

4.2 डेटा संग्रहण

- प्राथमिक डेटा: --मनरेगा श्रमिकों का सर्वेक्षण (n=500), ग्राम पंचायत मुख्यों के साक्षात्कार।
- माध्यमिक डेटा:-- सरकारी रिपोर्ट, पंचायत राज दस्तावेज, रोजगार एवं भुगतान रिकॉर्ड।

4.3 नमूना चयन

प्रत्येक विकासखंड से 100 मनरेगा श्रमिकों का यादृच्छिक चयन।

5. परिणाम — आर्थिक प्रभाव

5.1 रोजगार और आय में बदलाव

- अधिकांश श्रमिकों ने मनरेगा से स्थिर आय एवं कार्यालयीन अवसर प्राप्त किया।
- कृषि के अलावा अतिरिक्त आय स्रोत के रूप में मनरेगा की भूमिका उल्लेखनीय।

आर्थिक सुधार के संकेतक:--

- औसत मासिक आय में वृद्धि
- ऋण पर निर्भरता में कमी
- कृषि-बाह्य पूंजी निर्माण

5.2 महिला श्रमिकों की भागीदारी

- बाड़ी एवं ओबैदुल्लागंज में महिला श्रमिकों की भागीदारी अधिक रही।
- महिला-मुखी कार्यों में समान वेतन एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
- समान मजदूरी, कार्यस्थल पर उपस्थिति और बैंक-खाते के माध्यम से भुगतान ने महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाई।

6. परिणाम — सामाजिक प्रभाव

6.1 सामाजिक समावेशन

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों को रोजगार अवसरों में समान भागीदारी मिलती है।
- मनरेगा कार्यों में जातिगत भेदभाव कम हुआ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की भागीदारी से जातीय दूरी में कमी और सामुदायिक सहभागिता बढ़ी।

6.2 समुदायों में आत्म-सम्मान एवं स्वावलंबन

- ग्रामीण परिवारों में आत्म-सम्मान की भावना, बच्चों के लिए शिक्षा व्यय में वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार दिखा।

➤ स्थानीय कार्यों में सहभागिता से आत्म-सम्मान, शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया मजबूत हुई।

6.3 सामाजिक बुनियादी संरचना का निर्माण

मनरेगा के अधीन बने जल संरक्षण प्रकल्प, सड़कों, नालियों तथा भूमि संवर्धन कार्यों ने ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया।

7. तुलनात्मक विश्लेषण — पाँच विकासखंड

संकेतक	बाड़ी	ओबैदुल्लागंज	सांची	सिलवानी	उदयपुरा
रोजगार उपलब्धता	उच्च	बहुत उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम-उच्च
महिला भागीदारी	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च
सामाजिक समावेशन	अच्छा	उत्कृष्ट	संतुलित	अच्छा	अच्छा
कार्यान्वयन प्रभावकारिता	अच्छा	उत्कृष्ट	मध्यम	उच्च	मध्यम

8. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

8.1 नियमित भुगतान में देरी

कुछ पंचायतों में भुगतान तथा कार्य स्वीकृति में अनियमितता देखी गई।

8.2 कार्य गुणवत्ता एवं निगरानी

कुछ कार्यों की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं थी।

8.3 सूचना एवं प्रशिक्षण का अभाव

ग्रामीण श्रमिकों को योजनाओं के अधिकारों तथा योगदान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। सामाजिक अंकेक्षण की सीमितता

9. निष्कर्ष

मनरेगा ने रायसेन जिले के ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण तथा समावेशन, स्थानीय विकास और स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाँचों विकासखंडों में ओबैदुल्लागंज तथा बाड़ी में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पाया गया हालांकि भुगतान प्रक्रिया, प्रशिक्षण और निगरानी की चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। नीति-स्तर पर भुगतान-समयबद्धता और निगरानी सुदृढ़ करने से परिणाम और बेहतर हो सकते हैं।

10:-- सुझाव

1. भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना

पंचायत एवं प्रशासनिक स्तर पर भुगतान त्वरित किया जाए।

2. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम

कार्य-गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षण, श्रमिकों को कार्य गुणवत्ता एवं रोजगार कौशल का प्रशिक्षण उपलब्ध हो।

3. समावेशन सुधार हेतु सामाजिक कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण हेतु विशेष योजनाएँ। महिला-केंद्रित सुविधाएँ (क्रेच/छाया), सामाजिक अंकेक्षण का विस्तार

4. टेक्नोलॉजी का उपयोग

डिजिटल भुगतान, मोबाइल-आधारित अद्यतन स्वीकृति स्वरूप प्रयोग अधिक किया जाए। समयबद्ध डिजिटल भुगतान

संदर्भ (Indicative)

1. Government of India. (2005). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.

2. मिश्रा, र. (2018). ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी योजनाएँ*. दिल्ली: सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।
3. शुक्ला, अ. (2021). “मनरेगा का ग्रामीण समाज पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन”, भारतीय ग्रामीण अध्ययन जर्नल, 12(2), 45–60।
4. योजना आयोग (2013). ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार पर रिपोर्ट. नई दिल्ली।
5. भारत सरकार (2005). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम. नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2023). मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली।
7. भारत सरकार (2022). ग्रामीण विकास सांख्यिकी. नई दिल्ली।
8. शर्मा, एस. एल. (2016). भारतीय ग्रामीण समाज. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
9. देसाई, ए. आर. (2014). ग्रामीण भारत का समाजशास्त्र. मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन।
10. जिला पंचायत रायसेन (2024). मनरेगा कार्यान्वयन एवं प्रगति रिपोर्ट. रायसेन (म.प्र.)।
11. हिरेमठ, एस. (2017). “ग्रामीण रोजगार गारंटी और सामाजिक समावेशन”, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 9(1), 78–92।